



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 1989/ज्येष्ठ 5, 1911

No. 100]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 1989/JYAISTHA 5, 1911

इस भाग में मिलावट संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन को रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 26 मई, 1989

का. म. 22/1/89—वि. क. :—बिक्री कर और वित्त मंत्रालय
में सम्बन्धित अन्य मामलों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए
और 10 फरवरी, 1989 को नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों
के सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें माल के अन्तर-
राज्य प्रेषण पर कर लगाने तथा उससे सम्बन्धित विभिन्न तरीकों
और कुछ मुख्य मंत्रियों की एक समिति द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त के
तैयार किए जाने के बाद केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का माय-
लाय, दिए जाने वाली छूट प्रदान करने की शक्तियों के सम्बन्ध में
केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में भी सिकाश की
गई।

2. इस संकल्प के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने माल को
की एक समिति नियुक्त करने का फैसला किया है जिसका गठन इस
प्रकार से होगा :—

- | | |
|--|---|
| 1. श्री नारायण बल विहारी,
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश | अध्यक्ष |
| 2. श्री शरद पवार,
मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र | सदस्य |
| 3. श्री एम. करुणानिधि,
मुख्य मंत्री, तमिलनाडु | —बड़ी— |
| 4. श्री ज्योति बघु,
मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल | —बड़ी— |
| 5. श्री मोती लाल बोरा,
मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश | बड़ी |
| 6. श्री शिव चरण माथुर,
मुख्य मंत्री, राजस्थान
श्री के. जे. रेड्डी,
अपर सचिव, वित्त मंत्रालय,
राजस्व विभाग। | —बड़ी—
सचिव के रूप
में कार्य करेंगे |

3. इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

- (1) केन्द्र और राज्यों के साथ-साथ दिए जाने वाले छूट सम्बन्धी शक्तियों के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करना,
- (2) उनसे सम्बन्धित किसी अन्य बातों के बारे में सिफारिशें करना।

4. यह समिति अपने कार्य निष्पादन के बारे में अपनी ही प्रक्रिया तैयार करेगी और अपने अध्ययन के प्रयोजन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से यथावश्यक सूचना मांगेगी।

5. यह समिति अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 1989 तक प्रस्तुत करेगी।

के. जे. रेड्डी, भरर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 26th May, 1989

F.No. 22/1/89-ST.—The Chief Minister's Conference held at New Delhi on 9th and 10th February, 1989 to discuss Sales Tax and other matters relating to the Ministry of Finance had adopted a resolution recommending levy of tax on inter-State consignment of goods and various modalities connected thereto and also to the issue of guide lines by the Central Government with regard to the power of exemption to be concurrently vested with the Central Government and the State Governments, after these guidelines are formulated by a Committee of some Chief Ministers.

2. In pursuance of this Resolution, the Central Government has decided to appoint a Committee of Chief Ministers with the following composition :—

1. Shri Narayan Datt Tiwari,
Chief Minister of Uttar Pradesh Chairman

2. Shri Sharad Pawar,
Chief Minister of Maharashtra Member

3. Shri M. Karunanidhi,
Chief Minister of Tamil Nadu Member

4. Shri Jyoti Basu,
Chief Minister of West Bengal Member

5. Shri Moti Lal Vora,
Chief Minister of Madhya Pradesh Member

6. Shri Shiv Charan Mathur,
Chief Minister of Rajasthan Member
Shri K.J. Reddy, Additional Secretary, Ministry of Finance, Deptt. of Revenue will function as Secretary to the Committee.

3. The terms of reference of the Committee are as under :—

- (i) to formulate guidelines in regard to the power of exemptions to be concurrently vested with the Centre and the States;
- (ii) to make recommendations regarding any other related matters thereto.

4. The Committee will evolve its own procedure for its work and may, for the purpose of its study, call for such information as may be necessary from the Central and State Governments.

5. The Committee will submit its report by the 31st July, 1989.

K.J. REDDY, Addl. Secy.